टाइटल कोड - MPHIN37675
Email- haldharkisankgn@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

प्रधान संपादक - विवेक जैन

वर्ष 01 अंक 07 | सितम्बर 2022 | पृष्ठ-8 मूल्य -5.00 रूपये

18 को भोपाल में होगा कृषि आदान विक्रेता संघ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन

ऑनलाईन प्लेटफार्म पर खाद-बीज एवं कीटनाशक दवाईयों की बिक्री का प्रदेशभर के व्यापारी दर्ज करायेंगे विरोध

संघ के संगठन मंत्री विनोद जैन ने कहा- आंदोलन को कई कंपनियां कर रही समर्थन

हलधर किसान, भोपाल। मप्र कृषि आदान विक्रेता संघ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन 18 सितंबर को प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रदेशभर के व्यापारी शामिल होने जा रहे है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, यूपी के अध्यक्ष अतुल त्रिपाठी, मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल, संगठन प्रदेश सचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय रघुवंशी मौजूद रहेंगे।

संघ के प्रदेश संगठन मंत्री विनोद जैन, खरगोन जिलाध्यक्ष नरेंद्र चावला ने बताया कि खाद. बीज, कीटनाशक विक्रेता संघ सक्रिय एवं रजिस्टर्ड संगठन है। स मेलन में व्यापार शासन के नए नियमों, नीतियों से आ रही समस्याओं के अलावा खाद. बीज, कीटनाशक के लिए अभिशाप बन चुके ऑनलाईन कारोबार के खिलाफ एकजुट होकर विरोध दर्ज कराएंगे।

इन समस्याओं पर भी होगा मंथन

महामंत्री जैन ने बताया खेती को लाभ का धंधा बनाने में राज्य सरकार के उद्देश्य की पूर्ति करते हुए कृषकों की सहायता करते हुए अपना परिवार का भरण.पोषण करते हैं और उन्ही कंपनियों के माल का विक्रय करते हैं जिसको केंद्र और राज्य सरकार अनुमति प्रदान करती है और विधिवत लायसेंस प्राप्त कर ही उर्वरक एवं कीटनाशक का विक्रय किया जाता है। नियमानुसार कृषि विभाग से पल सरकारी लेब में टेस्ट करता है। परन्तु से पल के नमूने 1.2 प्रतिशत अमानक आने पर 2.3 माह से प्रदेश के विक्रेताओं पर एफआईआर की जा रही है जो कि अवैधानिक है।

हम विक्रेता हैं निर्माता नहीं, हम इस तरह की कार्यवाही को अब नहीं सहेंगे। कंपनी के मूल उत्पाद को अधिकृत विक्रेता से बिल से प्राप्त करके बिना छेड़छाड़ के विक्रय किया जाता है, तो अमानक होने पर विक्रेता को दोषी नहीं माना जा सकता। अगर कोई आदान अमानक आता है तो कंपनी पर एफआईआर होनी चाहिए। पूर्व में पूरे प्रदेश में जो प्रकरण में न्यायालय में गये हैं उन सभी में कोर्ट ने यह निर्णय दिया है।

मुख्य अतिथि
मनमोहन सिंह कलंत्री
राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया संघ

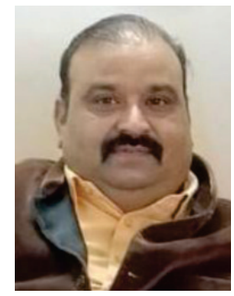

मानसिंह राजपूत
प्रदेश अध्यक्ष

विनोद जैन
प्रदेश संगठन महामंत्री

संजय रघुवंशी
प्रदेश सचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता

कई कंपनियां ऑनलाईन के विरोध में

महामंत्री जैन ने बताया कि ऑनलाईन के विरोध में संघ लगातार काम कर रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे है। हाल ही में ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बहिष्कार के लिए विभिन्न कंपनियों को पत्र लिखे गए थे। इस पत्र के जवाब में सल्फर मिल्स, जीएसपी ॅप साइंस, सुमिल केमिकल्स, और नागार्जुन (एनएसीएल)लिमिटेड सहित पूर्व में धानुका, सुमिटोमो केमिकल यूपीएल, अडामा, सहित अनेक क पनियों ने संघ को समर्थन पत्र जारी किया है कि वे अपने उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नहीं दंगे।

बीज भण्डार™

क्या आप अपना खुद का व्यापार स्थापित करना चाहते है ?

मध्य भारत की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन आउटलेट बीज भंडार की फ्रेंचाइजी ले और बने अपनी दुकान के मालिक

बीज भंडार की फ्रेंचाइजी लेने के लिए संपर्क करे।

बीज भंडार, जैन एग्रो एजेंसी, खरगोन मोबा. 8305103633

उन्नत खेती के उत्तम बीज

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही नकली उत्पादों की बिक्री पर लगे रोक : ऑल इंडिया संघ

हलधर किसान (98262 25025)

अहमदाबाद. भारत सरकार द्वारा कीटनाशकों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जो प्रावधान किया गया है उसके विरोध में ऑल इंडिया संगठन द्वारा अब पूरे देश में आंदोलन की तैयारी कर रही है।

ऑल इंडिया संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण भाई पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल जयपुर, मान सिंह राजपूत भोपाल, माफ्हा के सचिव विपिन कासलीवाल, अरविंद भाई पटेल सहित अनेक पदाधिकारी ने ऑनलाइन कीटनाशक बिक्री के खिलाफ देश में इसके खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद शहर आंदोलन का शंखनाद किया है। आयोजन में गुजरात के लगभग हर तालुका एवं जिले के लगभग 600 से ज्यादा व्यापारी भी उपस्थित थे। उपस्थित सभी व्यापारियों एवं वक्ताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि ऑल इंडिया संघ के सदस्यो द्वारा जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा व्यापारियों को कीटनाशक दिया जा रहा है वह उनका बहिष्कार करेंगे और स्थानीय डीलर से ही कीटनाशकों की खरीदी करेंगे।

इस बात पर भी चिंता जताई गई कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नकली उत्पादों की बिक्री की जा रही है उससे देश के किसानों को बड़ा घाटा होगा एवं देश के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जल्दी इस बारे में ऑल इंडिया संघ का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री एवं कृषि सचिव से मुलाकात करके इसे रोकने की कोशिश करेंगे। देश के प्रत्येक राज्य में इसका विरोध किया जाएगा एवं सभी राज्यों में कीटनाशक डीलरों द्वारा किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदी को जल्द से जल्द बंद कर दिया जावेगा। ऑनलाइन कीटनाशक बिक्री के खिलाफ खड़े हुए देशभर के व्यापारी सम्मेलन में पदाधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन कीटनाशक बेचने से होने वाले नुकसान की भरपाई किस प्रकार की जाएगी और नकली कीटनाशक आने पर उसकी रोकथाम कैसे की जाएगी? अमानक कीटनाशक होने पर कैसे जिम्मेदारी तय की जाएगी ? इसके बारे में केंद्र सरकार ने अभी तक कुछ नहीं बताया है।

सावधान! ऑनलाइन एप के जरिए बेचा जा रहा नकली उत्पादः ईओडब्ल्यू

नई दिल्लीः ईओडब्ल्यू के मुताबिक मुंबई के लोग गैर.मान्यता प्राप्त ऐप से अपनी दैनिक जरूरत के जो उत्पाद ऑनलाइन खरीदते हैं, उनमें से कई नकली होते हैं। ईओडब्ल्यू ने पिछले आठ महीने में दैनिक जरूरतों के रूप में इस्तेमाल होने वाली पांच करोड़ रुपये मूल्य की नकली कॉपीराइट वस्तुओं और खाद्य उत्पादों को जब्त किया हैण् इसके साथ ही 61 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ईओडब्ल्यू अपराध शाखा (सीबी) नियंत्रण इकाई के एक अधिकारी ने बताया कि कॉपीराइट उत्पादों से संबंधित 14 मामले और अन्य नकली उत्पादों के संबंध में 11 मामले मुंबई में दर्ज किए गए हैं।

99 प्रतिशत नकली उत्पाद

ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा गैर.मान्यता प्राप्त ऐप के माध्यम से खरीदे गए इन उत्पादों में से 99 प्रतिशत नकली हैं। लोग इसका शिकार होते हैं क्योंकि ऑनलाइन उपलब्ध माल की कीमत वास्तविक उत्पादों की तुलना में कम होती हैं।

कृषि मंत्री ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान के छठवें दीक्षांत समारोह में प्रदान किए डिग्री और पदक

कृषि-व्यापार के छात्र आत्मनिर्भर भारत के विकास में निभायेंगे महत्वपूर्ण भूमिकाः केन्द्रीय मंत्री तोमर

हलधर किसान। हैदराबाद. कृषि की अवधारणा को बदलने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के युग में फसलों में आने वाले बदलावों का अध्ययन करने के साथ.साथ कृषि रणनीति पर दोबारा काम करने की जरूरत बन गई है। कृषि में कैसे प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाया जाये, कैसे नई पीढ़ी को कृषि की तरफआकर्षित किया जाये ? सरकार इन सभी विषयों पर काम कर रही है। डिजिटल कृषि मिशन जैसी कई योजनायें शुरू की कई हैं। कृषि स्टार्ट.अप्स को भी और प्रोत्साहन दिया जायेगा।

यह बात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री नरेंद्र तोमर ने विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संगठन राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) हैदराबाद के छठवें दीक्षांत समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा भारत कृषि प्रधान देश है। हमने न केवल खेती की महत्ता और प्राथमिकता स्वीकार की है, बल्कि यह साबित किया है कि हमारी खेती विपरीत और जटिल परिस्थितियों में अपना लचीलापन कायम रखती है। विडंबना यह है कि कृषि आज भी मौसम पर निर्भर है। किसान मेहनत करता है, सरकार सब्सिडी देकर मदद करती है, उर्वरक उपलब्ध कराती है, बिजली और सिंचाई की व्यवस्था करती है, ताकि भरपूर फसल हो, लेकिन जब प्रकृति की मार पड़ती है, तो फसल में रोग लग जाता है, कभी ओले बरसते हैं, बाढ़ आ जाती है। हालांकि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों के नुकसान की भरपाई हो जाती है, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि इस परिस्थिति को बदला जाये।

इसमें स्नातकोत्तर प्रबंधन डिप्लोमा (कृषि.व्यापार प्रबंधन/पीजीडीएम एबीएम) के सफल 202 छात्रों को डिग्री तथा पदक प्रदान किये गये। समारोह में कषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा विशिष्ट अतिथि थे दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तोमर ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुये विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि को समृद्ध बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। खेती और किसानों को समृद्ध करने के प्रयासों के तहत, छात्र भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुये खेती को समय देकर देश के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मैनेज के छात्रों को किसान समुदाय की सेवा तथा आत्मनिर्भर भारत के लिये योगदान करते हुये गर्व का अनुभव होगा। किसानों के प्रशिक्षण के प्रबंधन का काम सफल है और उसकी ऊंची गुणवत्ता है। उन्होंने कहा, ऐसे कई संस्थान हैं, जो बेहतर तरीके और कुशलता से शिक्षा प्रदान करते हैं। यहां छात्र अपना उज्ज्वल भविष्य बनाते हैं। उन्हें अपने संस्थानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिये।

तीन वर्ष की बैच रही मौजूद

मैनेज के महानिदेशक डॉ. पी चंद्र शेखर ने कहा इस समय चलने वाले प्रशिक्षण, शोध परामर्श, नीतिगत समर्थन और एसी.एंड.एबीसी, डीएईएसआई, एसटीआरवाई और आरएएफटी, एआर जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अलावा हम अन्य गतिविधियां भी चलाते हैं, जो भारत को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायक हैं। हमें अपने छात्रों से आशा है कि वे दूसरे देशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों में कृषि अधिकारी बनकर भारतीय कृषि को सीमा पार तक ले जायेंगे। और भविष्य में मैनेज भारत में 200 से अधिक संगठनों में कृषि.व्यापार शिक्षा के मानक और गुणवत्ता में सुधार लायेगा।

इस अवसर पर मनोज आहूजा ने भी प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कार प्रदान किये। दीक्षांत समारोह 2022 में वर्ष 2018 से 22 तक की तीनों बैचेज के विद्यार्थी, शिक्षक-मंडल, स्टाफ और पुरस्कार व पदक विजेता छात्रों के माता-पिता भी सम्मिलित हुये।

60 से बढ़ाकर कि 100 सीटें

मैनेज में एक बहुविध सुविधा का भी उद्घाटन किया गया है, जिसका नामकरण आचार्य चाणक्य के नाम पर किया गया है। उन्होंने कहा कृषि-व्यापार शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए यह तय किया गया है कि मैनेज एबीएम के पीजीडीएम पाठ्यक्रम की सीटों को 60 से बढ़ाकर 100 कर दिया जाये। किसान समुदाय की सेवा करने में और आत्मनिर्भर भारत के विकास में अपनी भूमिका के महत्व को देखते हुये मैनेज के छात्रों को गर्व का अनुभव करना चाहिये। नियमित नौकरी के साथ-साथ आपको अपने देश के किसानों के कल्याण के लिये भी काम करना चाहिये।

नैनो यूरिया में मप्र के किसान दिखा रहे रुचि, छिड़कांव के लिए ड्रोन का हो रहा इस्तेमाल

हलधर किसान. (98262 25025)

मध्य प्रदेश के किसानों में नैनो यूरिया के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन का इस्तेमाल कर दवाई का छिडकांव किया जा रहा है, इसके लिए प्रशासन सहयोग कर रहा है। जानकारी अनुसार करीब 400 किसानों ने ड्रोन के जरिए इसका इस्तेमाल शुरू किया है। करीब एक हजार एकड़ कृषि क्षेत्र में नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है।

सूबे में खरीफ सीजन 2022 की शुरुआत में ही अब तक 6 लाख 7 हजार बोतल से अधिक नैनो तरल यूरिया की बिक्री हो चुकी है, जबकि रबी 2021.22 में 16 लाख 11 हजार लाख बोतल बिके थे, कम लागत और अधिक फायदे की वजह से किसान इसे अपना रहे हैं।

एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी देते हुए कृषि क्षेत्र में नैनो यूरिया के इस्तेमाल की तारीफ की। सीएम ने मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में संपन्न कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानते हुए इन कार्यों को देश में स्थापित करने के लिए भी प्रयास करने को कहा, उन्होंने कृषि क्षेत्र में नैनो यूरिया, फार्म गेट एक्ट की पहल और उन्नति एप के प्रयोग की भी तारीफ की।

प्राकृतिक कृषि पर होगा संवाद

सीएम ने बताया कि प्राकृतिक कृषि के इच्छुक किसानों के साथ शीघ्र ही संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें प्राकृतिक कृषि के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 59 हजार किसानों के रजिस्ट्रेशन और 28 हजार से अधिक किसानों को प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण देने के कार्य को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कृषि विविधीकरण के लिए मध्य प्रदेश में दो परियोजनाओं की स्वीकृति एक राष्ट्रीय उपलब्धि है। वर्तमान में आईटीसी द्वारा औषधीय अश्वगंधा और तुलसी के 4500 एकड़ क्षेत्र में उत्पादन के साथ ही ग्रीन एंड ग्रेस का जैविक सब्जियों और अनाज का 1235 एकड़ में उत्पादन काम शुरू हो गया है। चार अन्य परियोजनाओं पर परीक्षण का काम चल रहा है। इनमें विदिशा जिले में हरी मटर और धनिया, रीवा, सतना, ग्वालियर, देवास, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर में आलू उत्पादन, देवास में बांस उत्पादन और नर्मदापुरम, सीहोर एवं छिंदवाड़ा में संतरा और अमरूद का उत्पादन भी बढ़ाने का प्रयास है। अधिकारियों से कहा कि वे कृषि विविधीकरण में मध्य प्रदेश में किए गए ठोस प्रयास जारी रखें, उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3 साल में सरसों का उत्पादन दोगुना हो गया है। वर्तमान में 12 लाख 33 हजार हेक्टेयर में सरसों का उत्पादन हो रहा है।

भारत में हर साल भूमि क्षरण की वजह से पच्चीस लाख टन नाइट्रोजन, तेंतीस लाख टन फास्फोरस और पच्चीस लाख टन पोटाश की होती है क्षति

मृदा संरक्षण अभियान और बंजर होती जमीन के खतरे

संपादकीय

केंद्र सरकार की पहल पर मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन सन 1953 में हुआ था। तब से लाखों हेक्टेयर भूमि को उर्वर बनाया जा चुका है, लेकिन अभी भी इससे ज्यादा भूमि ऐसी है जिसे उपजाऊ बनाने की जरूरत है। औद्योगिकीकरण, वनीकरण और विकास की दूसरी परियोजनाओं की वजह से जमीन का रकबा भी घटता जा रहा है, साथ ही भूमि का क्षरण भी तेजी से हो रहा है। केंद्र सरकार ने मृदा क्षरण रोकने के लिए गांव.गांव में जागरूकता अभियान चलाए हैं। इसके अलावा मृदा संरक्षण के दूसरे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन यदि किसान भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पहल नहीं करेगा तो ये सारे अभियान सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि जिन कारणों से जमीन बंजर हो रही हैए उन कारणों पर गौर किया जाए और जमीन की उर्वरता बढ़ाई जाए।

केंद्र सरकार ने मृदा क्षरण रोकने के लिए गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाए हैं। इसके अलावा मृदा संरक्षण के दूसरे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन अगर किसान भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पहल नहीं करेगा तो ये सारे अभियान सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि जिन कारणों से जमीन बंजर हो रही है, उन कारणों पर गौर किया जाए और जमीन की उर्वरता बढ़ाई जाए। खेती.किसानी में रासायनिक खाद का इस्तेमाल कब शुरू हुआ, इसका इतिहास शायद ही कोई जानता हो। माना जाता है कि सबसे पहले सन 1840 के आसपास जर्मन वैज्ञानिक लिबिक ने खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के उपयोग की बात दुनिया के सामने रखी थी। बाद में दुनिया के तमाम कृषि वैज्ञानिकों ने उनके शोध को स्वीकारा। लिबिक ने कहा था कि अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश (एनपीके) की खाद बना कर खेतों में डाली जाए तो इससे फसलें तेजी से बढ़ सकती हैं।इस नए प्रयोग को दुनिया भर के किसानों ने अपनाया। लेकिन इसके लगातार इस्तेमाल ने मिट्टी की उर्वरता तो घटा ही दी, बल्कि करोड़ों हेक्टेयर जमीन को भी बंजर बना डाला। दुनिया भर में रेगिस्तानी क्षेत्र तेजी से फैल रहे हैं। मिट्टी की उर्वरता भी कम होती जा रही है। ऐसे में निर्जन रेगिस्तान में जीवन कैसे वापस लाया जाएए यह एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मृदा वैज्ञानिकों के मुताबिक मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट के चार बड़े कारण हैं। इनमें तेजी से होता औद्योगिकीकरणए कृषि में पानी का अत्यधिक इस्तेमाल, मवेशियों के लिए चरागाहों का जरूरत से ज्यादा दोहन और सूखे की बढ़ती मियाद।

आंकड़े बताते हैं कि रासायनिक खाद के बढ़ते इस्तेमाल से उर्वर और हरे.भरे भूमि क्षेत्र भी बंजर इलाकों में तब्दील होकर दुनियाभर में करीब एक अरब लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुके हैं। इसकी वजह से लाखों जैविक और वनस्पति प्रजातियों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। पेड़.पौधों की कई प्रजातियों का तो हमेशा के लिए खात्मा हो चुका है। करोड़ों लोग जो खेती.बागवानी के जरिए जिंदगी बसर कर रहे थेए उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। आंकलन बताते हैं कि इस सदी के मध्य तक धरती की एक चौथाई मिट्टी मरुस्थलीकरण से प्रभावित होगी। यह एक चिंताजनक पहलू है, लेकिन हालात और बिगड़ने के पहले ही स्थिति को संभालने के लिए यदि आगे आया जाए, तो इस विकट संकट से बचा जा सकता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारी मात्रा में बचे गोला.बारूद की रायायनिक सामग्रियों को एनपीके खाद और कीटनाशक बना कर बेचने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दुनिया भर में नया कारोबार खड़ा कर लिया था। इस कारोबार में कंपनियों को भारी मुनाफा होने लगा था और बाजार में इनकी जड़ें भी मजबूत हो चली थीं। ज्यादातर किसान इन कंपनियों द्वारा बनाई खादों पर इस कदर निर्भर होते गए कि इन खादों के बिना कोई फसल उगाते ही नहीं।

भारत और एशियाई देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद हरित क्रांति की शुरुआत हुई। खाद और कीटनाशकों का कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि बेहतर उपज लेने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरी है। इसके बाद देश के छोटे.बड़े किसान कीटनाशकों का इस्तेमाल इस कदर करने लगे कि जमीन की उर्वरता पर इसका बुरा असर पड़ने लगा। आज हालत यह है कि देश के लाखों किसानों की जमीन की उर्वरता इतनी कम हो गई है कि बिना बड़ी मात्रा में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के कोई भी फसल होती ही नहीं। कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग कई तरह की समस्याएं पैदा करता है। जमीन में जो जहरीलापन बढ़ता जा रहा हैए वह कई बीमारियों का कारण बन रहा है। इससे मिट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का संतुलन भी बिगड़ गया है। इससे किसान नई.नई समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने नीम के लेप वाली यूरिया को रासायनिक खाद का विकल्प बताया है। लेकिन इस संबंध में यह जानना जरूरी है कि इसके इस्तेमाल से मिट्टी और जीव.जंतुओं पर कितना बुरा असर पड़ रहा है।

मिट्टी को लेकर हुए तमाम शोधों से यह सामने आया है कि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कार्बनए आक्सीजन और हाइड्रोजन थोड़ी मात्रा में रहना चाहिए। लेकिन न्यून मात्रा में इसमें लोहा, गंधक, सिलिका, क्लोरीन, मैगनीज, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, तांबा, बोरान और सेलेनियम की मौजूदगी भी जरूरी है। गौरतलब है कि कुदरत अपने हिसाब से इन तत्वों की भागीदारी तय करती है, पर इंसान की गतिविधियों की वजह से इन सारे तत्वों का संतुलन गड़बड़ा गया है।

दिलचस्प बात है कि मिट्टी में नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में भी रहती है और अकार्बनिक रूप में भी। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से अमोनियम के साथ जीवाणु क्रिया करते हैं और अंतत: जीवाणुओं से एंजाइम का निर्माण होता है। दूसरे तत्वों की भी अपनी खास भूमिका है। कैल्शियम पौधे के तने को मजबूत करता हैए तो फास्फेट फूल और फल के लिए लाभदायक होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। हाइड्रोजन और आक्सीजन पौधों को मिट्टी में समाए हुए पानी से मिलता है। इन प्राकृतिक तत्वों के आधार पर ही तय होता है कि मिट्टी कैसी है। ज्यादा अम्लता और ज्यादा क्षारीयता, दोनों ही पौधों के लिए नुकसानदायक होते हैं।

कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल भूमि क्षरण की वजह से पच्चीस लाख टन नाइट्रोजन, तेंतीस लाख टन फास्फोरस और पच्चीस लाख टन पोटाश की क्षति होती है। यदि इस क्षरण को बचा लिया जाए तो हर साल करीब साठ हजार लाख टन मिट्टी की ऊपरी परत बचेगी और इससे हर साल करीब पचपन लाख टन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा बचाई जा सकेगी। केंद्र सरकार की पहल पर मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन सन 1953 में हुआ था। तब से लाखों हेक्टेयर भूमि को उर्वर बनाया जा चुका है, लेकिन अभी भी इससे ज्यादा भूमि ऐसी है जिसे उपजाऊ बनाने की जरूरत है। औद्योगिकीकरण, वनीकरण और विकास की दूसरी परियोजनाओं की वजह से जमीन का रकबा भी घटता जा रहा है, साथ ही भूमि का क्षरण भी तेजी से हो रहा है। केंद्र सरकार ने मृदा क्षरण रोकने के लिए गांव.गांव में जागरूकता अभियान चलाए हैं। इसके अलावा मृदा संरक्षण के दूसरे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन यदि किसान भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पहल नहीं करेगा तो ये सारे अभियान सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि जिन कारणों से जमीन बंजर हो रही हैए उन कारणों पर गौर किया जाए और जमीन की उर्वरता बढ़ाई जाए।

भारत में मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों में कमी गत चार दशकों से ज्यादा पाई गई। शुरुआत में केवल नाइट्रोजन की कमी थी, लेकिन कटाव, जलभराव, बहुत अधिक कीटनाशकों व रासायनिक खादों का प्रयोग और एक फसल चक्र में जरूरत से ज्यादा फसलों को उगाने जैसे तमाम कारणों की वजह से मिट्टी की उर्वरता घटती गई। आज हालात यह हो गई कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के बावजूद अच्छी पैदावार नहीं हो पा रही है। ऐसे में जागरूक किसानों ने मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफरुख किया है। इसमें न तो कीटनाशकों का प्रयोग होता है और न ही रासायनिक खादों का। कंपोस्ट, हरी और जैविक खाद का प्रयोग कर देश के तमाम किसान मिट्टी की सेहत सुधारने में लगे हैं। लेकिन जहां प्राकृतिक खेती नहीं हो रही है, वहां मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने व संरक्षण का कार्य करना बड़ी चुनौती है।

यूपी के 62 जिलों में लगेंगे 2100 नवीन राजकीय नलकूप, योगी सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

हलधर किसान (98262 25025)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद ने रबी सीजन से पहले राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा और महत्वपुर्ण फैसला लेते हुए 62 जिलों में 2100 नवीन राजकीय नलकूप लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा कम वर्षा वाले जिलों के किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त तोरिया (सरसों) के बीज बांटे जाने का भी फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन ;मुख्यमंत्री कार्यालयद्ध में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

बैठक के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस परियोजना पर 839 करोड़ रुपये से अधिक खर्च आएगा। यह योजना इसी वर्ष से शुरू होकर 2023.24 के अंत तक पूर्ण हो जाएगी। इससे सभी किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। एक नलकूप 50 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई कर सकेगा। इस परियोजना से एक लाख पांच हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इन नलकूपों के निर्माण में श्रमिकों के द्वारा 31 लाख मानव दिवस सृजित होंगे। सिंचाई की कठिनाइयों की दृष्टि से राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सरसों का बढ़ेगा उत्पाद - कृषि मंत्री

यह प्रयास किया जाएगा कि चयनित किसानों में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस सुविधा का लाभ पहले आओ.पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर दिया जाएगा। शाही ने कहा कि कम वर्षा वाले जिलों के किसानों को यह बीज प्राथमिकता पर दिए जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों ;सांसदों.विधायकों, ग्राम प्रधानों की उपस्थिति में यह वितरित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इससे चार लाख क्विंटल अतिरिक्त सरसों का उत्पादन राज्य में कर सकेंगे।

मुफ्त बांटेंगे सरसों के बीज

कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कमजोर मानसून को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद ने तोरिया के बीज के दो किलोग्राम वाले मिनी किट का नि:शुल्क वितरण करने का फैसला किया है। ऐसे में दो लाख मिनी किट वितरित किए जाएंगे। 4000 क्विंटल तोरिया के बीज वितरित किए जाएंगे और इसमें चार करोड़ 57 लाख 60 हजार रुपये खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि यह पूर्ण खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। शाही ने बताया कि निशुल्क वितरण में लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी और जिलों में 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों तथा शेष अन्य किसानों में वितरित किया जाएगा।

प्रतियां पाने, लेख प्रकाशन के लिए संपर्क करें

हलधर किसान, राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र की प्रतियां प्राप्त करने के लिए अपना नाम, डाक पता और फोन नंबर सहित संपर्क करें। साथ ही कृषि, पशुपालन, बागवानी, अनुसंधान जैसे क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, शोध, खेती में नवाचार जैसे लेख प्रकाशन कराना चाहते है तो हमें वाट्सएप नंबर- 8305103633, 94254 89337 पर भेजे सकते है। हम आपका लेख प्रमुखता से फोटो सहित उचित स्थान पर प्रकाशित करेंगे।

बीज भण्डार™

भारत में तेजी से बढती हुई रिटेल चैन आउटलेट

सभी कंपनियों के उत्कृष्ट क्वालिटी के बीज मिलने का एक मात्र स्थान

मार्केट मूल्य से कम कीमत पर बीज उपलब्ध

बीज भंडार के सीड कार्ड का विमोचन करते हुए माननीय कृषि मंत्री
मध्यप्रदेश शासन श्री कमल जी पटेल एवं खरगोन विधायक श्री रवि जी जोशी

आज ही बीज भंडार में अपनी सदस्यता दर्ज कीजिए और पाइए
आपका स्मार्ट कार्ड – सीड कार्ड।
इतना ही नहीं आपको मिलेंगे सभी कंपनियों
के उच्चतम क्वालिटी के बीज और साथ ही
अर्जित होंगे आपकी हर खरीदी पर अंक।

इसके अलावा कई उत्पादों पर

आकर्षक और विशेष डिस्काउंट

डाउनलोड करें : Google play | अधिक जानकारी के लिए YouTube पर देखें : Beej Bhandar, KisanPlusTv | फॉलो :

ब्रांच-खरगोन/खंडवा/ कुक्षी/बडवाह/राजपुर/अंजड/ धामनोद
इंदौर/ जबलपुर/ मंडलेश्वर/ मनावर/ बरगी/ कसरावद

बीज भंडार की फ्रेंचाईसी लेने के लिए संपर्क करे - 8305103633, 7879428271

भारत में हर साल नाईट्रोजन युक्त उर्वरकों से 16.6 करोड़ टन ग्रीनहाउस गैसों का हो रहा है उत्सर्जन

उर्वरकों के रूप 1.8 करोड़ टन नाइट्रोजन का इस्तेमाल, जो कि जलवायु के लिए बड़ा खतरा है

हलधर किसान। आज दुनिया भर पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि में बड़े पैमाने पर सिंथेटिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। इनमें सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक भी एक हैं। यह सही है कि इन उर्वरकों ने दुनिया भर में पैदावार को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है लेकिन साथ ही इन उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल ने पर्यावरण, स्वास्थ्य और जलवायु के लिए बड़ी समस्याएं भी पैदा कर दी हैं। वैश्विक स्तर पर केवल नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उपयोग से हर साल 113 करोड़ टन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जोकि जलवायु के लिए एक बड़ा खतरा है। उत्सर्जन का यह खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह कृषि क्षेत्र से होने वाले कुल उत्सर्जन का करीब 10.6 फीसदी हिस्सा है जबकि ग्रीनहाउस गैसों के वैश्विक उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी करीब 2.1 फीसदी है।

यदि भारत से जुड़े आंकड़ों को देखें तो चीन के बाद भारत दूसरा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को इस्तेमाल करने वाला देश है, जोकि हर साल करीब 1.8 करोड़ टन नाइट्रोजन का इस्तेमाल उर्वरकों में कर रहा है। वहीं चीन में यह आंकड़ा 2.81 करोड़ टन है। देखा जाए तो भारत जितने नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहा है उनसे करीब 16.6 करोड़ टन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। जोकि वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों से होने वाले उत्सर्जन का करीब 15 फीसदी हिस्सा है। वहीं चीन की हिस्सदारी करीब 28 फीसदी है।

अंतराष्ट्रीय जर्नल साइंटिफिक रिपोर्टस में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक यदि सिंथेटिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की सप्लाई चेन से होने वाले ग्रीनहाउस उत्सर्जन को अलग.अलग बांट कर देखें तो 113 करोड़ टन ग्रीनहाउस गैसों में से करीब 38.8 फीसदी का उत्सर्जन उत्पादन के कारण हो रहा है। वहीं इसके कृषि में उपयोग से करीब 58.6 फीसदी उत्सर्जन होता है जबकि बाकी 2.6 फीसदी उत्सर्जन के लिए दुनिया भर में इनको लाने ले जाने के कारण हो रहा उत्सर्जन जिम्मेवार है।

एफएओ द्वारा की गई गणना के अनुसार सिंथेटिक उर्वरकों में मौजूद नाइट्रोजन की कुल वैश्विक खपत 2018 में 10.8 करोड़ टन तक पहुंच गई थी। चीन, भारत, अमेरिका, यूरोप और ब्राजील इसके करीब 68 फीसदी हिस्से का उपयोग कर रहे हैं। वहीं यदि मिस्र और मॉरीशस को छोड़ दें तो अन्य अफ्रीकी देश इसकी बहुत कम मात्रा ही उपयोग कर रहे हैं। भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप इसके 62 फीसदी उत्सर्जन के लिए हैं जिम्मेवार।

अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में कृषि के लिए किए जा रहे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उपयोग और उनसे होने वाले उत्सर्जन का राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक डाटासेट भी तैयार किया है। इस रिसर्च से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि इस उत्सर्जन में भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप की हिस्सेदारी करीब 62 फीसदी है।

इसी तरह जर्नल नेचर में छपे एक अन्य शोध से पता चला है कि नाइट्रोजन उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के कारण वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर औद्योगिक काल से पहले की तुलना में करीब 20 फीसदी बढ़ चुका है। वहीं इसमें हो रही वृद्धि की बात करें तो यह हर दशक 2 फीसदी की दर से बढ़ रही है।

क्या है नुकसान

गौरतलब है कि जब नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को मिट्टी में डाला जाता है तो पौधे उसका केवल एक हिस्सा ही ग्रहण करते हैं। जबकि उसका दूसरा हिस्सा मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा सोख लिया जाता है जो अपने मेटाबोलिज्म की मदद से उसे नाइट्रस ऑक्साइड में बदल देते हैं। वहीं उस स्थान पर मौजूद नाइट्रोजन का एक अन्य हिस्सा वहां से पानी की मदद से बह जाता है या फिर वाष्प में बदल कर वातावरण में घुल जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जलवायु के दृष्टिकोण से कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह ग्रीनहाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में तीन सौ गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। साथ ही यह हमारे जीवनकाल से भी ज्यादा समय तक वातावरण में बनी रह सकती है।

2050 तक 50 फीसदी बढ़ जाएगा इन उर्वरकों का उपयोग

अनुमान है कि खाद्य प्रणलियों की वजह से हर साल 5.400 करोड़ टन से ज्यादा ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन एफएओ का अनुमान है कि 2019 में कृषि से होने वाला उत्सर्जन बढ़कर 1.070 करोड़ टन प्रति वर्ष तक पहुंच गया है। समस्या सिर्फ मौजूदा उत्सर्जन ही नहीं है, एफएओ का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर जिस तरह से नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग बढ़ रहा है उसके चलते 2050 तक इसके उपयोग में 50 फीसदी की वृद्धि होने की आशंका है।

उर्वरको का कम उपयोग ही है उपाय

ऐसे में यह जरुरी है कि हम जितना हो सके कृषि को सस्टेनेबल बनाने का प्रयास करें। उर्वरकों के उपयोग में कमी ऐसी ही एक पहल है जो इस दिशा में सार्थक हो सकती है। समस्या इन उर्वरकों के बेतहाशा बढ़ते उपयोग के कारण पैदा हुई है। ज्यादा पैदावार के लालच में किसान ज्यादा से ज्यादा सिंथेटिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं जो वातावरण में जहर बनकर घुल रहा है। जैविक खेती ऐसा ही एक विकल्प है जो न केवल पैदावार में वृद्धि के साथ.साथ पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसके माध्यम से किसान न केवल पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं बल्कि अपनी मेहनत की सही फल भी पा सकते हैं।

क्यों किया प्रतिबधित?

मंत्री ने कहा कि ये कीटनाशक चावल, विशेष रूप से बासमती चावल के निर्यात और खपत में संभावित बाधा बन रहे थे। कीटनाशकों को पंजाब में साठ दिनों की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि बिना किसी अवशिष्ट प्रभाव वाले अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल का उत्पादन किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इन कीटनाशकों का इस्तेमाल बासमती चावल उत्पादकों के हित में नहीं है।

हरियाणा और पंजाब ने 10 कीटनाशकों इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध

हरियाणा सरकार ने राज्य के अंदर 10 कीटनाशकों की बिक्री, स्टॉक, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा सरकार ने कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के एक अनुरोध के बाद लिया है। असल में खाद्य उत्पादों के निर्यात का काम करता है, लेकिन, बीते महीनों में कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण बासमती की निर्यात खेप खारिज होने संबंधी कई शिकायतें मिली थी। इन कीटनाशकों का उपयोग ज्यादातर बासमती धान के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार ने शुद्ध बासमती उत्पादन के उद्देश्य से कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया है। असल में बासमती की निर्यात खेप में अधिक कीटनाशक पाए जाने के बाद बीते महीनों में उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। जिसके बाद बासमती धान को कीटनाशक मुक्त करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले पंजाब सरकार ने भी 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

पंजाब में इन दस इंसेक्टीसाइड्स पर प्रतिबंध

पंजाब सरकार ने बासमती फसल के लिए 10 कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह सुगंधित चावल के निर्यात में कृषि.रसायन बाधा बन रहे थे। कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने कीटनाशकों की बिक्री, स्टॉक और वितरण को रोकने के निर्देश जारी किए हैं। प्रतिबंधित कीटनाशकों में एसेफेट, बुप्रोफेजिन, क्लोरोपायरीफॉस, मेथैमिडोफोस, प्रोपिकोनाजोल, थियामेथोक्सम, प्रोफेनोफोस, आइसोप्रोथियोलेन, कार्बेन्डाजिम, ट्राईसाइक्लाजोल शामिल है।

बीज भंडार

हमारे यहाँ पर सभी कम्पनियों के उच्च क्वालिटी की सब्जी बीज एक ही छत के निचे उचित दाम पर मिलते है

ब्रांच : खरगोन/खंडवा/कुक्षी/ बडवाह/ राजपुर/अंजड/ धामनोद/ इंदौर/जबलपुर/ मंडलेश्वर/ मनावर/ बरगी/ कसरावद

बीज भंडार की फ्रेंचाईसी लेने के लिए संपर्क करे - 8305103633, 7879428271

देश में लांच हुई पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस

हलधर किसान .(98262 25025)

देश में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की दिशा में शासन. प्रशासन के साथ वैज्ञानिक भी नित नए प्रयास कर रहे है। इसकी कड़ी में देश को पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बस की पुणे में शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत की। इस बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और निजी कंपनी केपीआईटी लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. कहा कि स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने और नए उद्यमियों और नौकरियों के सृजन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हरित हाइड्रोजन एक उत्कृष्ट स्वच्छ ऊर्जा वेक्टर है जो रिफाइनिंग उद्योग, उर्वरक उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और भारी व्यावसायिक परिवहन क्षेत्र में होने वाले सबसे अधिक उत्सर्जन को डीकार्बोनाइजेशन करने में सक्षम बनाता है।

भारत में लंबी दूरी के मार्गों पर चलने वाली एक डीजल बस आमतौर पर सालाना 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) का उत्सर्जन करती है और भारत में ऐसी दस लाख से अधिक बसें हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाली बसें डीजल बस द्वारा होने वाले इस कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर लगाम लगाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

वैज्ञानिकों ने कहा कि ईंधन सेल वाले वाहनों की उच्च दक्षता और हाइड्रोजन के अधिक ऊर्जा घनत्व यह सुनिश्चित करती है कि ईंधन सेल ट्रकों और बसों के लिए प्रति किलोमीटर परिचालन लागत डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में कम है और यह भारत में माल ढुलाई के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। इसके अलावा, ईंधन सेल वाहन शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का तकनीकी कौशल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और बहुत कम लागत की है। डीजल से चलने वाले भारी व्यावसायिक वाहनों से लगभग 12 से 14 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन और कण उत्सर्जन होता है। ये विकेंद्रीकृत उत्सर्जन हैं और इसलिए इसे पाना मुश्किल है।

उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन इस क्षेत्र से सड़क पर होने वाले उत्सर्जन को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत माल ढुलाई और यात्री यातायात के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों में वृद्धि करने का भी लक्ष्य बना रहा है। उन्होंने कहा इन लक्ष्यों को प्राप्त करके, भारत जीवाश्म ऊर्जा के शुद्ध आयातक से स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक बन सकता है और इस तरह हरित हाइड्रोजन उत्पादक और हाइड्रोजन के लिए उपकरणों का बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर भारत हाइड्रोजन अंतरिक्ष में दुनिया भर में नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

शिक्षक दिवस विशेष...

18 विद्यालयों की स्थापना कर और महिला समाज के लिए प्रेरणा बनी थी प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले

5 सितंबर को शिक्षक दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। गुरु को हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया गया है। शिक्षकों के सम्मान के इस दिन पर आपको देश की पहली महिला अध्यापिका, नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेत्री, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री सावित्रीबाई फुले के बारे में बताने जा रहे है। बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए जिन्होंने समाज का कड़ा विरोध झेला, कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों के पत्थर भी खाने पड़े।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रुप में मनाते आ रहे हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति रहे वह भारतीय संस्कृति के संवाहक प्रख्यात शिक्षाविद् महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे उनके इन्हीं गुणों के कारण सन् 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारतर से सम्मानित किया था। 1962 के पहले शिक्षक दिवस की प्रथा नहीं थी, पर जब डॉक्टर राधाकृष्णन के विद्यार्थियों ने 5 सितंबर को उनका जन्म दिवस मनाने का आग्रह किया तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने देश के सभी शिक्षकों को उनकी शैक्षणिक प्रतिभा को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दे दिया। तब से 5 सितंबर 1962 को प्रथम शिक्षक दिवस मनाया गया, तब से आज तक हमारे बौद्धिक सृजन करता हमारे शिक्षकों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस हर साल बड़े उत्साह से मनाया जाता है।

वर्तमान परिपेक्ष में अगर हम स्त्री शिक्षा की बात करें तो सन 1962 से पहले सन 1831 में भारत को प्रथम महिला शिक्षिका मिली थी, आज शिक्षक दिवस पर महिला शिक्षा की अलख जगाने वाली पहली महिला शिक्षिका के महिला शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य समस्त महिलाओं को गौरवान्वित करते हैं। यहां स्मरणीय है सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को नया गांव में हुआ सावित्रीबाई भारत की प्रथम महिला शिक्षिका समाज सुधार का एवं मराठी कवियत्री थी। आपने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए, रूढ़िवादी सोच के जमाने में सावित्रीबाई ने स्त्री शिक्षा को लेकर जो कदम उठाएं उसमें निश्चित ही कितने सामाजिक पारिवारिक विरोधियों का सामना करना पड़ा होगा, यह आज हमारे लिए अकल्पनीय है, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सर्व समाज की बालिकाओं के लिए शिक्षा का अलख जगाने में पूरे जोश के साथ जुटी रही और 3 जनवरी 1848 में पुणे में पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। इस तरह के 5 और विद्यालय खुले फिर यह म चलता रहा और उन्हें तत्कालीन सरकार से अपने कार्य के लिए सम्मान भी प्राप्त हुआ, दुःख तो तब होता था जब. जब भी सावित्रीबाई स्कूल जाती तो लोग उनसे नाराज होकर उन पर पत्थर और गोबर फेंकते थे पर वो अपने इरादे पर अटल रही और उन्होंने 18 विद्यालयों की स्थापना करी और भारत के महिला समाज के लिए प्रेरणा बनी। समाज सेवा के चलते भारत में फैली प्लेग जैसी महामारी में निःस्वार्थ भाव से बिना अपनी जान की परवाह करें जन सेवा में लगी रही और की अंत में प्लेग की चपेट में आने से 10 मार्च 1897 को आपने अंतिम सांस ली।

आज हम भारत की प्रथम महिला शिक्षिका को शिक्षक दिवस पर हृदय से सम्मान देते हैं। वर्तमान में भारत में महिलाओं में जो अकल्पनीय शैक्षणिक विकास देखा जा रहा है वह निश्चित ही सावित्री बाई जी को फक्र महसूस कराता होगा। आपकी प्रेरणा एवं मजबूत इरादों से आज उच्च शिक्षित महिला वर्ग का चौतरफा विकास भारत देश को विश्व पटल पर गौरवान्वित कर रहा है।

बरखा विवेक बड़जात्या बाकानेर
जिला-धार (मप्र)

2 अक्टूबर से 'भारत' ब्रांड से बिकेगा फर्टिलाईजर

वन नेशन वन फर्टिलायजर योजना होगी लागू

हलधर किसान

नई दिल्ली। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से देश में केवल भारत ब्रांड के नाम से उर्वरक बेचे जाएंगे। यह घोषणा रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने करते हुए बताया कि उर्वरक सब्सिडी योजना 'प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना' के तहत नई पहल वन नेशन वन फर्टिलाइजर की शुरुआत की जा रही है। यूरिया और डीएएफसहित सभी सब्सिडी वाले उर्वरक अक्टूबर से सिंगल ब्रांड 'भारत' के तहत बेचे जाएंगेए जिसका उद्देश्य किसानों को मिट्टी के पोषक तत्वों की समय पर उलब्धता सुनिश्चित करना और माल ढुलाई सब्सिडी को कम करना है।

पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए साल के अंत तक का समय

मंडाविया ने कहा कि कंपनियों को केवल अपना नाम, ब्रांड, उनके बैग के एक तिहाई स्थान पर लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति है। शेष दो तिहाई हिस्से पर भारत ब्रांड और पीएमबीजेपी का लोगो दिखाना होगा। कंपनियों को अपना पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए साल के अंत तक का समय दिया गया है।

सब्सिडी बिल बढ़कर 2.25 लाख करोड़ होने का अनुमान

पिछले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने 1.62 लाख करोड़ रुपये का उर्वरक सब्सिडी बिल वहन किया। पिछले पांच.छह महीनों में वैश्विक

कीमतों में तेज वृद्धि देखते हुए सरकार का सब्सिडी बिल चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस योजना को शुरू करने के पीछे के तर्क के बारे कहा कि सरकार यूरिया के खुदरा मूल्य का 80 प्रतिशत, डाय.अमोनियम फॉस्फेट ;डीएपीद्ध का 65 प्रतिशत, एनपीके का 55 प्रतिशत और पोटाश के म्यूरेट के 31 प्रतिशत कीमतों पर सब्सिडी देती है। माल ढुलाई सब्सिडी भी सानाना 6000.9000 करोड़ रुपये की सीमा प्रदान की जाती है। हालांकि, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार देशभर में विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित उर्वरकों के विनिर्देश समान हैं, उत्पादों का निर्माण और विपणन विभिन्न राज्यों में विभिन्न ब्रांडों के तहत किया जाता।

माल ढुलाई सब्सिडी का सरकार पर बढ़ रहा बोझ

मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों में उर्वरकों की एक क्रोस.मूवमेंट है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्वों के परिवहन में देरी हो रही है और सरकार पर माल ढुलाई सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए सहकारी समीतियों इफको और क्रिबको की उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं लेकिन वे परिवहन के जरिए राजस्थान और मध्यप्रदेश में अपने उत्पादों की बिक्री करती हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की राजस्थान में एक विनिर्माण इकाई है लेकिन मध्यप्रदेश में अपने उत्पाद बेचती है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की मध्यप्रदेश में एक इकाई है लेकिन यह उत्तर प्रदेश में बिक्री करती है। कुछ मामलों में देश के पूर्वी क्षेत्र में विपणन के लिए पश्चिमी भारत में उर्वरकों का निर्माण किया जाता है।

एक ब्रांड पेश करने के पीछ क्या है तर्क

मंडाविया ने कहा, एकल ब्रांड पेश करने के पीछे का पूरा विचार इस क्रॉस मूवमेंट को रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां अपने उत्पादों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नजदीक बेच दे और अनावश्यक परिवहन से बचे।

यह पहल उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाएगी और बिना किसी रुकावट के आपूर्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगीए उर्वरक आपूर्ति में एकरूपता लाएगी, कंपनियों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करेगी और माल ढुलाई सब्सिडी के बोझ को कम करेगी।

कांग्रेस और कंपनियां कर रही विरोध

उर्वरक कंपनियों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर उनके ब्रांड वैल्यू और बाजार में दूसरी उर्वरक कंपनियों की अपेक्षा उनके उत्पाद की अलग पहचान को खत्म कर देगा। सरकार का कहना है कि यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके आदि के लिए सिंगल ब्रांड नाम क्रेमशः भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके होगा। इन उर्वरक बोरियों पर उर्वरक सब्सिडी योजना अर्थात प्रधान मंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को दर्शाने वाला एक लोगो इस्तेमाल किया जाएगा।

सोयाबीन की फसल पर केवडा रोग की मार, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे किसान

हलधर किसान. एक बार फिर खरीफ फसलों पर मौसम की मार पड़ते नजर आ रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में इन दिनों सोयाबीन की फसल केवड़ा रोग की चपेट में आ गई है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरते नजर आ रहा है। किसान अब शासन. प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे है। ज्यादातर नांदेड में शिकायत सामने आ रही है।

किसानों का कहना है कि जून में बारिश की लंबी खेंच फिर जुलाई हुई लगातार बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। अगस्त में भी बारिश का दौर जारी रहा। नतीजतन सोयाबीन की फसल पर रोगों की मार पड़ रही है। महाराष्ट्र में खरीफ मौसम की मुख्य फसल सोयाबीन पर केवडा रोग लग रहा है। इससे फसल खराब हो रही है। किसानों के नुकसान के बावजूद इस पर काबू पाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही।

फसलों पर बढ़ रहा है रोग का प्रकोप

बारिश शुरू होने के बाद खरीफसीजन की फसलों की वृद्धि तेजी से हो रही थी। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों पर कीटों का प्रभाव बढ़ रहा है। जिले में अब केवडा रोग के प्रकोप से किसानों के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। सोयाबीन में फूल आने के दौरान वातावरण अच्छा हो तो उत्पादन बढ़ता है, लेकिन पानी की अधिकता और धूप के प्रकोप से उत्पादन सीधे तौर पर प्रभावित होगा। वहीं दूसरी ओर गर्मी भी बढ़ रही है, इसलिए अब किसानों को जल प्रबंधन के साथ.साथ इस बीमारी से भी निपटना होगा।

कृषि विभाग ने क्या कहा ?

कृषि विभाग किसानों को सलाह दे रहा है कि केवडा रोग के प्रकोप से बचने के लिए खेती के लिए उपलब्ध प्रमाणित प्रतिरोधी बीज आवश्यक है। कृषि विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की सलाह पर ही दवा का छिड़काव करें। खाद और जल प्रबंधन बहुत जरूरी है। इस रोग के प्रकोप को कम करने के लिए संक्रमित फसल के अवशेषों को जमीन में दबा देना चाहिए।

कहां पर किसानों को है बारिश का इंतजार

इस साल जुलाई से 15 अगस्त के बीच नादेड़ जिले में राज्य में सबसे भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण न केवल फसल बल्कि कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ऊपर क्षेत्रों में अच्छी बारिश के कारण फसलें अच्छी थीं। अब बढ़ती गर्मी के चलते कई क्षेत्रों में पानी की जरूरत महसूस हो रही है। अगर जल्द ही बारिश नही हुई तो फसलों का नुकसान होना तय है। करीब 15 दिन पहले कुछ स्थानों पर अधिक बारिश के कारण फसल पानी में डूब गई थी, लेकिन अब वहीं ऊपरी क्षेत्रों में जहां पानी का रुकाव नहीं है वहां पर फसलें बिना पानी के नष्ट हो रही हैं।

मप्र में बढ़ेगी मूंग खरीदी लिमिट, कृषि मंत्री पटेल ने केंद्रिय कृषि सचिव से मुलाकात के बाद कि घोषणा

हलधर किसान। मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राहत वाली खबर है। प्रदेश में फसल खरीदी की लिमिट 25 क्विंटल से बढ़ाकर अब 40 क्विंटल तक खरीदी कि जा सकेगी। मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की सहमति से यह निर्णय लिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि सचिव भारत सरकार मनोज आहूजा से चर्चा के उपरांत जारी एक बयान में कही है। मंत्री पटेल ने बताया कि मूंग खरीदी की मात्रा प्रति किसान 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल करने पर केंद्रीय सचिव ने सहमति जताई है और जल्द ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे।

किन जिलों में हो रही मूंग की खरीद

मध्यप्रदेश प्रमुख मूंग उत्पादक राज्यों में आता हैए यहां पर बड़ी मात्रा में मूंग की फसल की खेती की जाती है, मध्य प्रदेश के 32 जिलों में मूंग की फसल हेतु 234750 किसानों ने 6 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की फसल का पंजीयन करवाया है। मूंग की खरीदी हेतु टोटल 741 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, इस वर्ष मूंग की खरीदी सरकार द्वारा काफी समय के बाद चालू की गई है, ऐसे में कई जरूरतमंद किसानों ने तो ओने/ पौने दाम पर ही मूंग बेच दिए हैं।अब सरकार ने खरीदी की लिमिट बढ़ाकर किसानों को राहत दे रही है, जिससे किसानों का आक्रोश थोड़ा कम होगा।

मार्च में ही खरीदी का दिया सुझाव

कृषि मंत्री पटेल ने केंद्रीय सचिव को बताया कि किस प्रकार वन ग्रामों की फसलों का बीमा मध्यप्रदेश में किया गया। केंद्र सरकार को यह सुझाव भी दिया कि जिस प्रकार मध्यप्रदेश में वन ग्रामों की फसलों का बीमा करा कर किसानों की फसलों की क्षति पूर्ति की राशि किसानों को दिलवाई गई। उसी प्रकार पूरे देश भर के वन ग्रामों की फसलों का बीमा करा कर देश के वन ग्रामों की फसलों का बीमा कराया जा सकता है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रत्येक वर्ष मार्च माह में ही चना, सरसों, मसूर की खरीदी करने का भी केंद्रीय सचिव को सुझाव दिया।

रबी सीजन में किसानों को मिलेगी राहत, मात्र 2 घंटे में उपलब्ध होंगे नए ट्रांसफार्मर

हलधर किसान.

मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली कंपनी ने एक माह बाद प्रारंभ होने वाले रबी सीजन की प्रभावी तैयारी कर मालवा.निमाड़ के सभी 15 जिलों की सिंचाई व्यवस्था के लिए 12 हजार ट्रांसफार्मर का अग्रिम स्टॉक रखा है। पात्रतानुसार मात्र 2 घंटे में ट्रांसफार्मर जारी कर दिए जायेंगे, जिससे रबी का सिंचाई कार्य प्रभावित न हो।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि क्षेत्र के सभी जिलों में ट्रांसफार्मर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ट्रांसफार्मर में खराबी आने की सूचना के बाद जल्दी ही इन्हें बदला जायेगा। उन्होंने बताया कि कंपनी क्षेत्र में 13 लाख से ज्यादा किसानों को रबी सीजन में सिंचाई के लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली वितरित की जायेगी। इस बार सिर्फ रबी सिंचाई के लिए लोड सवा तीन हजार मेगावाट के पार पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर में किसी कारण से खराबी आने पर कम से कम समय में पात्रतानुसार बदला जायेगा। श्री तोमर ने बताया कि कंपनी के स्थाई ट्रांसफार्मर डिपो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार, बड़वाह में कुल 8 हजार ट्रांसफार्मर का स्टॉक रहेगा। इसी तरह रबी सीजन के लिए बने अस्थाई डिपो देवास, आगर, शाजापुर, मनासा, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर में आवश्यकतानुसार 300 से 600 ट्रांसफार्मर का स्टॉक हर वक्त उपलब्ध रहेगा।

मध्य प्रदेश में 143 लाख हेक्टेयर में हुई बुआई

हलधर किसान।

भोपाल। मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन में करीब 143 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई के आंकड़े सामने आए हैं, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 96 फीसदी है। गत वर्ष इस अवधि में 144.33 लाख हेक्टेयर में बुआई हो गई थी। राज्य में प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन की बुआई 50.18 लाख हेक्टेयर में हुई है जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 4 लाख हेक्टेयर कम है। वहीं धान की बुवाई 32.20 लाख हेक्टेयर में

हो गई है। मक्का, उड़द, मूंग एवं कपास की बुवाई लक्ष्य को पार कर गई है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफफसलों का सामान्य क्षेत्र 138.52 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 147.72 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध 26 अगस्त तक 143.03 लाख हे. में बुआई होने के आंकड़े तैयार किए गए है। प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बुआई अब तक 50.18 लाख हेक्टेयर में हो गई है जबकि 54.42 लाख हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है। गत वर्ष इस अवधि में सोयाबीन 55.14 लाख हेक्टेयर में बुआई हो गई थी। दूसरी प्रमुख फसल धान की बोनी अब तक 32.20 लाख हेक्टेयर में हुई है जबकि लक्ष्य 34.71 लाख हेक्टेयर रखा गया है गत वर्ष इस अवधि में धान 38.52 लाख हेक्टेयर में बोयी गई थी। इस वर्ष धान का रकबा अब तक 6 लाख हे. कम है।

अन्य फसलो की स्थिति

प्रदेश में अब तक मक्का की बुवाई 16.14 लाख हेक्टेयरए तुअर 4.37 लाख हेक्टेयर, उड़द 16.90 लाख हेक्टेयर, मूंगफली 4.50 लाख हेक्टेयर एवं कपास 6.25 लाख हे. में बोई गई है। राज्य में अब तक कुल अनाज फसलें 54.31 लाख हेक्टेयर में, दलहनी फसलें 23.30 लाख हेक्टेयर में एवं तिलहनी फसलें 59.18 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं।

स्वागत...वंदन...अभिनंदन... स्वागत...वंदन...अभिनंदन... स्वागत...वंदन...अभिनंदन...

म.प्र. कृषि आदान विक्रेता संघ भोपाल

दिनांक 18/09/2022, दिन रविवार

प्रादेशिक सम्मेलन में पधारे हुए सभी अतिथियों एवं व्यापारियों का हार्दिक स्वागत... वंदन...

अभिनंदन!

मुख्य अतिथि
कमल जी पटेल
कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश शासन

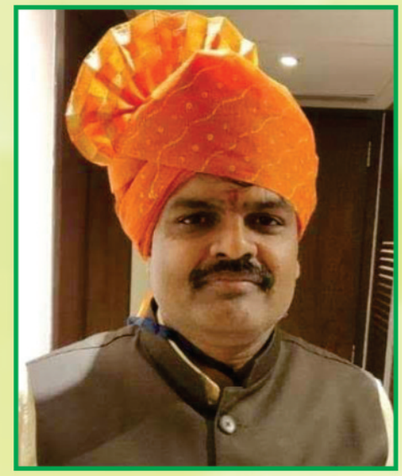

विशेष अतिथि
मनमोहन सिंह जी कलंत्री
राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया संघ

मान सिंह जी राजपूत
प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

विनोद जी जैन
प्रदेश संगठन महामंत्री

संजय जी रघुवंशी
प्रदेश सचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन। Titel Code. MPHIN/2022/37675, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।